भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 6 * दि. 16 से 31 अगस्त 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

पानी पर सियासत सूर्या प्रोजेक्ट को लेकर सरनाईक और मेहता आमने-सामने

मीरा भाईंदर. मीरा भाईंदर के 15 लाख से अधिक नागरिकों की प्यास बुझाने वाली महत्वाकांक्षी सूर्या प्रादेशिक जलापूर्ति परियोजना अब सियासी अखाड़ा बन गई है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और उनकी कंपनी मे. सेवन इलेवन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड पर परियोजना में अड़ंगा डालने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं, मेहता ने इन आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताते हुए पलटवार किया है. सरनाईक ने अपने पत्र में कहा है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस सूर्या जल परियोजना का शिलान्यास किया था, वह आज भी अधूरी है. उनका आरोप है कि कुछ लोग अपने व्यावसायिक हितों को जनहित से ऊपर रखकर करोड़ों रुपये की इस परियोजना में बाधा पैदा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे शहर को पानी की कमी के रूप में भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि घोड़बंदर रोड क्षेत्र में करीब 5.7 किलोमीटर लंबी मुख्य जल पाइपलाइन बिछाने का कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन वर्सोवा स्थित आरसीसी ब्रिज का निर्माण रुके होने से पूरी परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है. सरनाईक ने पत्र के साथ 12 जून 2026 को हुई एमएमआरडीए की संयुक्त बैठक का वृतांत भी संलग्न किया है.

3 वर्षों से अटकी पड़ी परियोजना

सरनाईक के मुताबिक बैठक में होटल तक पहुंच बनाए रखने के लिए रोड ग्रेडिएंट, एक्सेस रोड और अन्य तकनीकी मांगों पर सहमति बन गई थी. इसके बावजूद सिर्फ 98 मीटर का कार्य शेष रहने से पूरी परियोजना पिछले 3 वर्षों से अटकी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया

कि इसी तरह की बाधाओं के कारण पहले मीरा-भाईंदर मेट्रो परियोजना भी प्रभावित रही. सरनाईक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि यदि संबंधित कंपनी सहयोग नहीं करती तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन अधिग्रहित कर आरसीसी ब्रिज का निर्माण तत्काल पूरा कराया जाए, ताकि शहर को जल्द सूर्या बांध का पानी मिल सके.

सरनाईक सिर्फ आरोप लगाते हैं: मेहता

सरनाईक के आरोपों पर भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि आरसीसी ब्रिज का आधा निर्माण पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जारी है. परियोजना रोकने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है. मेहता ने कहा कि प्रताप सरनाईक को बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत है. उन्हें पहले अपने विभाग के अधूरे व उद्घाटन के बाद भी लंबित पड़े कार्यों का हिसाब देना चाहिए. मेहता ने दावा किया कि भाजपा और वे स्वयं सूर्या परियोजना को पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और किसी भी स्तर पर काम में बाधा नहीं डाली जा रही है.

अब सीएम फडणवीस के पाले में फैसला

सूर्या जल परियोजना को लेकर सत्ता पक्ष के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच खुले आरोप-प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है. एक ओर मंत्री प्रताप सरनाईक मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप और जरूरत पड़ने पर भूमि अधिग्रहण की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विधायक नरेंद्र मेहता सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं. ऐसे में अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैसले पर टिकी हैं. क्योंकि यह मामला केवल राजनीतिक आरोपों का नहीं, बल्कि मीरा-भाईंदर के लाखों नागरिकों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है.

दिसंबर शुरू होगी मेट्रो !

मेट्रो-9 के दूसरे चरण का सफल ट्रायल

भाईंदर : मीरा-भाईंदर से मुंबई आने-जाने वाले हजारों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. मेट्रो लाइन-9 के दूसरे चरण का करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष हिस्से में मेट्रो ट्रेन का वास्तविक ट्रायल भी सफलतापूर्वक शुरू हो गया है. एमएमआरडीए को उम्मीद

है कि सभी तकनीकी और सरकारी स्वीकृतियां समय पर मिलने पर पूरी मेट्रो लाइन वर्ष 2026 के अंत तक यात्री सेवा के लिए खोल दी जाएगी. काशीगांव और साईबाबा नगर स्टेशन के बीच मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण के बाद भाईंदर पश्चिम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान स्टेशन तक भी सफल ट्रायल रन हुआ. अधिकारियों के अनुसार इस पूरे रूट पर बिजली आपूर्ति शुरू हो चुकी है और ट्रैक, सिग्नलिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की अंतिम जांच जारी है.

यात्रा होगी सुविधाजनक

मेट्रो लाइन-9 का पहला चरण अप्रैल में दहिसर से काशीगांव के बीच शुरू किया गया था. इस सेवा को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है और प्रतिदिन 35 से 40 हजार यात्री इसका उपयोग कर रहे हैं.

अब काशीगांव से भाईंदर पश्चिम तक के दूसरे चरण का कार्य अंतिम दौर में है.

एमएमआरडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सफल ट्रायल और सभी आवश्यक स्वीकृतियों के बाद अंतिम चरण को दिसंबर तक जनता के लिए खोलने की योजना है.

इसके शुरू होने से मीरा-भाईंदर और मुंबई के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक होगी

साथ ही पश्चिमी उपनगरों में सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा.

बिजली लाइनों की वजह से रुका था काम

इस बीच पटरियां बिछाने, स्टेशन परिसर के विकास और अन्य तकनीकी कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं. भाईंदर पश्चिम के शहीद भगत सिंह गार्डन मेट्रो स्टेशन का निर्माण उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के कारण रुका हुआ था, लेकिन सरकार और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद यह बाधा दूर हो गई है. अब इस स्टेशन का शेष निर्माण भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है.

6 किलोमीटर का हिस्सा हो चुका है चालू

दहिसर से भाईंदर पश्चिम तक बनने वाली 10.41 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन-9 पर कुल 8 स्टेशन हैं. पहले चरण में दहिसर, पांडुरंग वाड़ी, मीरागांव और काशीगांव स्टेशन तक लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा चालू हो चुका है.

24 तरह की मशीनरी और वाहनों के लिए मंगाई गईं निविदाएं

बुलडोजर का बिल कौन भरेगा

भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ने अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अति-खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए करीब 9 करोड़ रुपए का ई-टेंडर जारी किया है. 3 साल तक चलने वाली इस व्यवस्था के तहत मनपा भारी मशीनरी, वाहन, चालक और ऑपरेटर किराए पर लेगी. हालांकि, सवाल यह है कि तोड़क कार्रवाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली मनपा अवैध निर्माणकर्ताओं से कार्रवाई का खर्च वसूलने के मामले में कितनी गंभीर है? पूर्व में की गई तोड़क कार्रवाई के डेमोलिशन बिल जारी करने और उनकी वसूली को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से मनपा के राजस्व की क्षति हो रही है. आर्थिक दबाव से जूझ रही मनपा के लिए एक तरफ मशीनरी किराए का खर्च बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई का खर्च संबंधित अवैध निर्माणकर्ताओं से वसूल नहीं होने पर दोहरा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.

किराए पर लिए जाएंगे ट्रेलर

मनपा के अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण उन्मूलन विभाग ने कार्रवाई के लिए 24 प्रकार की मशीनरी और वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं. ठेकेदार को प्रतिदिन 8 घंटे के आधार

पर मशीनरी के साथ आवश्यक चालक और ऑपरेटर उपलब्ध कराने होंगे. बहुमंजिला इमारतों को गिराने के लिए हाई-रीच जॉ क्रशर मशीन, 300 लॉन्ग-बूम पोकलेन ब्रेकर, जेसीबी 3 डीएक्स, 50 टन क्रेन, 12 टन हाइड्रा और 16 टन फराना जैसी भारी मशीनरी शामिल है. इसके अलावा आरसीसी स्लैब कटर, गैस कटर, ट्रैक्टर ब्रेकर, पिकअप, टेंपो, ट्रक, हाइवा डंपर, टोइंग वैन, ट्रैक्टर-ट्रॉली, 50 केवीए जनरेटर और ट्रेलर भी किराए पर लिए जाएंगे.

संपादकीय

लालच का जानलेवा खेल

पंजाब स्थित नवांशहर के एक गांव में ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हारने के सदमे में एक युवक व दो किशोरों का जहर खा लेना विचलित करने वाली घटना है। बाद में युवक व एक किशोर की मौत हो गई। निस्संदेह, ऑनलाइन गेम के लालच में किशोर-युवा विवेक खो देते हैं। लत लगाने वाले ये जहरीले खेल सुनहरे सपने तो दिखाते हैं, लेकिन हकीकत बेहद खुरदरी है। कहना कठिन है कि ऑनलाइन खेलों को कितने पारदर्शी तरीके व ईमानदारी के साथ संचालित किया जाता है। बहुत संभव है कि ये गेम भी ऑनलाइन फ्रॉड संस्कृति का ही हिस्सा हों, जो संचालकों के मुनाफे के लिये ही संचालित होते हों। बहरहाल, किशोर व युवक द्वारा मोटी रकम हारने के बाद खुदकशी करना परिवार, समाज व देश की बड़ी क्षति है। आखिर 21 साल व पंद्रह साल की उम्र कितनी होती है? पूरा जीवन सामने होता है। जीवन चंद रुपये हारने से ज्यादा कीमती होता है। छोटी हार के बाद बड़ी जीत की संभावनाएं बनी रहती हैं। विडंबना ही है कि हम हादसों में मरने वालों की संख्या को महज एक आंकड़े की तरह देखते हैं। लेकिन इस आत्मघात से इन परिवारों जो चोट पहुंची होगी, उसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। एक बच्चे को जन्म देने से लेकर पालने-पोसने तक माता-पिता पूरा जीवन लगा देते हैं। उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। मगर जब बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं तो परिवार पूरी तरह टूट जाता है। बच्चा तो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन परिवार को रोज तिल-तिल कर मरने को छोड़ देता है। दरअसल, आज मोबाइल दुधारी तलवार जैसे हो गए हैं। सूचना-संवाद तो देते हैं, साथ ही तमाम आघातों की आशंकाएं भी रहती हैं। जो मोबाइल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई और संवाद के लिये दिये जाते हैं, उसका दुरुपयोग बच्चे ऑनलाइन गेमिंग व वर्जित सामग्री देखने के लिये करने लगे हैं। पुरानी पीढ़ी बेबस है कि वे बच्चों की निगरानी कैसे करें? वे पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं?

दरअसल, देश-दुनिया में नई पीढ़ी के जीवन में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। नित नई तकनीक हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही है, लेकिन हम उसके नकारात्मक दुष्प्रभावों से बच नहीं पा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति समाज में इतनी गहरे तक घर कर गई है कि हर कोई रातों-रात अमीर बनने के सपने देखने लगा है। सोच है कि जैसे-तैसे पैसा कमाकर अमीर बना जाए। नवांशहर की घटना में पंद्रह साल के किशोर को आखिर क्यों ऑनलाइन गेमिंग से कमाई करने की ललक पैदा हुई? गेम खेलना बुरी बात नहीं है लेकिन उसका लत बनना घातक है। ये किशोर के खेलने-खाने की उम्र थी, लेकिन मैदान के खेल। लेकिन लालच के गेम में उलझकर आखिर वह क्या पाना चाह रहा था? जाहिर है पंद्रह साल के बच्चे की पढ़ाई-लिखाई से लेकर अन्य खर्चे तक मां-बाप ही उठाते हैं। आशंका हो सकती है कि किशोर परिवार के किसी व्यक्ति के खाते से रकम निकालकर ऑनलाइन गेमिंग में हार गए हों। फिर परिवार की सख्त प्रतिक्रिया के भय से ही उन्होंने आत्महत्या करने का दुखद फैसला लिया हो। बहरहाल, तकनीक के जरिये तेजी से बदलती दुनिया में बच्चों का सामंजस्य स्थापित करना अभिभावकों के लिये बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुरानी पीढ़ी के मां-बाप बच्चों की खुशी के लिये उन्हें मोबाइल व इंटरनेट की सुविधा तो उपलब्ध करा देते हैं, मगर इसके घातक प्रभावों की वे भी कल्पना नहीं कर पाते। कोई मां-बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा बुरी आदत का शिकार बने, लेकिन यार-दोस्तों की संगत में रहकर वे अकसर भटक जाते हैं। इस घटना में 21 साल के युवक के साथ पंद्रह साला दो बच्चों का भी जहर खाना कई सवालों को जन्म दे जाता है। आखिर क्या युवक के साथ किशोर भी ऑनलाइन गेमिंग की लत के शिकार थे? क्या उन्होंने अपने घर से पैसे लाकर युवक को ऑनलाइन गेमिंग में बाजी लगाने को दिए? फिर गेम हारने पर पैसा गंवाने के भय से उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया? बहरहाल, केंद्र व राज्य सरकारों को पैसे वाली ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के लिये गंभीर पहल करनी चाहिए। ताकि फिर किसी परिवार के फूल न मुर्झाएं।

बेरोजगारों का आक्रोश बढ़ाती शैक्षिक विसंगतियां

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 20 से 29 वर्ष की आयु के लगभग एक करोड़ दस लाख युवा स्नातक बेरोजगार हैं। इस स्थिति के दो अर्थ हो सकते हैं—एक तो यह कि प्रार्थी ज्यादा हैं और रोजगार है नहीं, और दूसरा यह कि स्नातक तक की पढ़ाई के दौरान उन्हें जो पढ़ाया गया है वह उन्हें किसी रोजगार के लायक नहीं बनाता।

कुछ ही दिन पहले राजधानी दिल्ली में युवा आक्रोश का एक नमूना देखा था देश ने। युवाओं की 'कॉकरोच पार्टी' ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाकर ही दम लिया था। फिर ऐसा ही आक्रोश झारखंड की राजधानी में पहुंचा। पिछले लगभग दो सप्ताह से रांची में युवा आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से उनकी बातचीत तो हुई, पर बात बनी नहीं। सरकार ने दावा किया है कि युवाओं की नब्बे प्रतिशत मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। जो दस प्रतिशत बची हैं उनमें से कुछ न्यायालय में विचाराधीन हैं। पर छात्र (युवा) मान नहीं रहे। अपने दावे के अनुसार वे राज्य की विधानसभा को घेर तो नहीं पाये, पर वहां तक पहुंच अवश्य गए।

उधर सरकार भी डट गई है। पता नहीं क्यों वह बची हुई दस प्रतिशत मांगें, जिनमें प्रमुख मांग मामले को सीबीआई के सुपुर्द करने की है, स्वीकार नहीं कर पा रही। शायद आप तक यह सब पहुंचने तक विवाद का कोई हल भी निकल आए। लेकिन, समस्या मात्र एक विवाद की नहीं है। कहीं अधिक गंभीर है मामला—समस्या युवाओं के आंदोलनी तेवरों के कारण समझने की है। युवाओं की हताशा और आक्रोश को समझने की आवश्यकता है। यह अनायास ही नहीं हुआ कि देश में सब तरफ युवा-आक्रोश की बात होने लगी है। एक अर्से से यह गुस्सा भीतर ही भीतर पनप रहा था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पता नहीं क्या सोच कर देश के युवाओं की तुलना तिलचट्टों (कॉकरोचों) से कर दी और उन्हें परजीवी घोषित कर दिया। सात समंदर पार बैठे एक भारतीय युवक को कुछ खल गया और उसने मज़ाक-मज़ाक में एक कॉकरोच पार्टी बना डाली। शायद यह उसे भी नहीं पता था कि उसका यह कदम देश के युवाओं की पीड़ा की अभिव्यक्ति बन जाएगा। बहुत तीखी और पीड़ादायक अभिव्यक्ति थी यह। जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ और अब रांची में जो कुछ हो रहा है या फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों की जिस गूंज को स्वर दे रहे हैं और आरएसएस के प्रमुख जिन युवाओं को अपनी पीढ़ी से अधिक ईमानदार और देशभक्त बता रहे हैं, यह सब कुल मिलाकर देश के युवाओं की पीड़ा को ही उजागर करने वाला है।

यह सही है कि इस सारे प्रकरण की शुरुआत नीट जैसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली का कारण बनी। यह भी सही है कि यह धांधली अपने आप में कोई छोटी समस्या नहीं है। पर देश का युवा जिस समस्या से जूझ रहा है वह कहीं अधिक जटिल और गहरी है। हताश है देश का युवा। वह जब नीट जैसी परीक्षाओं में बैठता है तो उसकी आंखों में एक सुनहरे भविष्य का सपना होता है। बहुत पीड़ा होती है जब ऐसा कोई सपना टूटता है। और यह पीड़ा तब और गहरी हो जाती है जब वह यह पाता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कुछ ग़लत तत्व, कोई ग़लत व्यवस्था और कुछ ग़लत नीतियां उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार हैं। वह समझ नहीं पाता कि उसका अवसर की समानता का अधिकार कोई कैसे छीन लेता है; सारी ज़रूरी योग्यताओं के बावजूद वह बेकारी से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पाता?

हां, बेकारी एक बड़ा कारण है हमारे देश के युवाओं की पीड़ा और आक्रोश का। सरकार भले ही कैसे और कितने ही दावे करती रहे अच्छे दिनों के, पर देश के युवा पथराई आंखों से इंतजार कर रहे हैं उन दिनों और उन स्थितियों का जब उनके दिन अच्छे होंगे। हकीकत यह है कि 15 से 24 आयु वर्ग के हमारे युवा आज एक गंभीर आर्थिक-सामाजिक चुनौती बन गए हैं। हमारे पास युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। यह संख्या हमारी ताकत होनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य से आज यह अपने आप में एक समस्या है। हम यह कह कर अपने आप को कुछ दिलासा दे सकते हैं कि हमारी युवा बेरोज़गारी की दर (10.2 प्रतिशत) दुनिया की बेरोजगारी दर से कम है। दुनिया की युवा बेरोजगारी दर 15.6 प्रतिशत है।

हमारे देश में कुल बेरोजगार आबादी का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा युवाओं का है। इन बेरोजगारों में एक बड़ा हिस्सा पढ़े-लिखे युवाओं का है। दुर्भाग्य है कि यह पढ़ाई रोजगार की दृष्टि से उनके बहुत काम की नहीं है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 20 से 29 वर्ष की आयु के लगभग एक करोड़ दस लाख युवा स्नातक बेरोजगार हैं। इस स्थिति के दो अर्थ हो सकते हैं—एक तो यह कि प्रार्थी ज्यादा हैं और रोजगार है नहीं, और दूसरा यह कि स्नातक तक की पढ़ाई के दौरान उन्हें जो पढ़ाया गया है वह उन्हें किसी रोजगार के लायक नहीं बनाता। दोनों ही अर्थ अपने आप में डराने वाले हैं। यह स्थिति हमारी उद्योग-नीति और शिक्षा-नीति दोनों पर सवालिया निशान लगाती है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति वर्ष 80 लाख से 1 करोड़ स्नातक तैयार होते हैं। इनमें से लगभग 15 लाख विद्यार्थी हर साल केवल इंजीनियरिंग क्षेत्र से होते हैं।

दूसरा सवाल उपयुक्त शिक्षा का है, जिसका सीधा रिश्ता उस पाठ्यक्रम से है जो हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। इंफोसिस के सह-संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ति के अनुसार भारत के अधिकांश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सीधे तौर पर नौकरी के योग्य नहीं होते। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि कॉलेज की शिक्षा और वास्तविक उद्योगों की जरूरतों के बीच एक बड़ा अंतर है। यहीं यह तथ्य जानना भी रोचक होगा कि पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर हमारे केरल में सर्वाधिक है—और हकीकत यह भी है कि देश के किसी भी राज्य की तुलना में केरल में साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज्यादा लगभग शत-प्रतिशत! स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा-नीति में कोई बुनियादी कमी है, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती जनसंख्या के मेल ने हमारे युवाओं की समस्याओं को बढ़ा दिया है। इन तीनों के कारण देश के युवाओं को सही और उचित काम नहीं मिलता, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं। उनकी निराशा धीरे-धीरे हताशा में बदलती जाती है। इस स्थिति के जो भी परिणाम हो सकते हैं, वे हमारे सामने हैं। ऐसे में युवाओं पर उंगली उठाना या फिर उन्हें कॉकरोच, परजीवी अथवा राष्ट्र-विरोधी आदि कहना अपने आप में किसी अपराध से कम नहीं है।

इन दिनों देश में, और शेष विश्व में भी, युवा पीढ़ी (जेन जी और जेन अल्फा) को लेकर कई स्तरों पर बहस चल रही है। दिल्ली के जंतर-मंतर और रांची के युवा-आंदोलनों को 'एक बिगड़ी हुई युवा पीढ़ी की हताशा की अभिव्यक्ति' कहने वालों की भी कमी नहीं है। और ऐसे भी हैं जो इन 'बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे' देखते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का कथन कुछ हैरान करने वाला है—पर सुखद हैरानी है यह। जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह प्रदर्शनकारी युवाओं को राष्ट्र-विरोधी नहीं मानते। विरोध-प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी उनकी पीढ़ी से अधिक सजग है, यह आदेश मानने के बजाय तार्किक जवाब चाहती है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध जताना संवाद का एक तरीका है जो आम सहमति बनाने में मदद करता है। मोहन भागवत की यह स्वीकारोक्ति हैरान इसलिए करती है कि उनकी इस टिप्पणी से दो-तीन दिन पहले ही आरएसएस के उनके वरिष्ठ सहयोगी ने जंतर-मंतर का हवाला देते हुए आज की युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सुना दिया था। सच बात तो यह है कि हमारी 'जेन जी' पीढ़ी सोच और व्यवहार दोनों को नई दिशा देने वाली है। आवश्यकता उसकी आलोचना करने की नहीं, उसे परजीवी मानने की नहीं, उसे समझने की है। यह पीढ़ी जो है, जैसी है, उसकी भर्त्सना करने से बात नहीं बनेगी, बात तब बनेगी जब हम उसके सोच की अनगढ़ता के बजाय उसके भीतर की सकारात्मकता को जानने-समझने की कोशिश करें। कब करेंगे हम यह कोशिश, यह हमें सोचना है।

परीक्षा की घड़ी

ऐसे वक्त में जब नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने से उपजे छात्र आक्रोश से देश हाल ही में दो-चार हुआ है, देश के परीक्षा सिस्टम पर प्रतिभागियों का भरोसा कायम करना अपरिहार्य शर्त है। हाल के वर्षों में केंद्रीय स्तर और राज्यों में विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षाएं स्थगित होने और परीक्षा परिणामों को लेकर किंतु-परंतु होने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। ऐसे में विश्वसनीयता के सवालों से जूझ रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का इंटेलिजेंस, कानून लागू करने वाली एजेंसियों तथा डिफेंस फोर्सेज के अनुभवी लोगों को अपने परीक्षा सुरक्षा कमांड सेंटर में शामिल करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। ये प्रयास दूसरी ओर हमें यह भी बताते हैं कि देश में महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं कितनी संवेदनशील व असुरक्षित हो गई हैं। नए प्रावधानों के अनुसार इसके टेस्ट सिक्योरिटी और लाइव ऑपरेशन्स अनुभाग के प्रस्तावित जनरल मैनेजर परीक्षा प्रक्रिया के लगभग हर संवेदनशील हिस्से की देखरेख करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नपत्र तैयार करने, एन्क्रिप्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वितरण और रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी शामिल रहेगा। विश्वास किया जाना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी निगरानी और परीक्षा के उपरांत डेटा एनालिसिस से परीक्षा व्यवस्था के पारदर्शी व विश्वसनीय होने की उम्मीद की जा सकती है। निस्संदेह, नीट प्रवेश परीक्षा विवाद के उपरांत प्रतिभागियों में भरोसा कायम करने की दिशा में यह एक गंभीर कोशिश होती नजर आती है। लेकिन एक बात तो तय है कि सिर्फ तकनीक के जरिए सिस्टम की खामियां दूर नहीं की जा सकतीं। हालिया नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई की जांच में एनटीए के अपने ही गोपनीय विभाग में खामियां पाई गई थीं, मसलन संतोषजनक ढंग से तलाशी न लेना, सीसीटीवी की अपर्याप्त निगरानी, जिम्मेदारियों का सही बंटवारा न होना तथा अंतिम प्रश्न सेट तक बहुत अधिक लोगों की पहुंच होना, जिसने परीक्षा प्रश्नपत्र के लीक संकट को जन्म दिया।

मेयर और प्रशासन पर साधा निशाना

मीरा- भाईंदर में गड्ढों पर 'शिवसेना स्टाइल' प्रदर्शन

भाईंदर मीरा भाईंदर शहर में सड़कों की बदहाल स्थिति, फाउंटेन होटल से गायमुख तथा ठाणे-घोड़बंदर रोड पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के विरोध में गुरुवार को शिवसेना ने काशीगांव मेट्रो स्टेशन से आक्रामक प्रदर्शन किया. जिला प्रमुख राजू भोईर के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में शिवसैनिक और स्थानीय नागरिक शामिल

हुए, जिसमें जिला संगठक निशा नार्वेकर, विधानसभा प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह, नवीन सिंह, संदीप तिवारी, दीप काकड़े, मनोज राणे, संतोष गोले, रामभवन शर्मा, सुनील केसरी, प्रीति पाटिल, मुस्तफा वनारा, पूर्व नगरसेविका, नगरसेवकों का समावेश था. शिवसैनिकों ने सड़क पर उतरकर प्रतीकात्मक रूप से गड्ढे भरते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. शिवसेना ने आरोप लगाया कि मनपा में भाजपा की सत्ता के दौरान मेयर द्वारा घोड़बंदर रोड की मरम्मत नहीं कराने संबंधी पत्र दिए जाने के कारण लाखों नागरिकों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है.

नहीं की गई प्रभावी कार्रवाई

मेयर की कार्यशैली को गैर-जिम्मेदार बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की. प्रदर्शन के दौरान शिवसेना पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस और ट्रैफिक विभाग की बैठक में सड़क के गड्ढे तत्काल भरने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मनपा प्रशासन ने इस पर अमल नहीं किया. उनका आरोप है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बावजूद प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है. शिवसेना ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जानलेवा गड्ढों की मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. मेयर, मनपा आयुक्त और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की भी मांग उन्होंने की.

चलती बस का निकला पहिया

बसों की फिटनेस, सर्विसिंग व सुरक्षा जांच पर सवाल

30 से ज्यादा यात्री बाल-बाल बचे

मीरा-भाईंदर, (सं.) मीरारोड पूर्व के कनकिया परिसर में रविवार को महानगरपालिका परिवहन उपक्रम की चलती बस का अचानक पहिया निकल जाने से हड़कंप मच गया. घटना के समय बस में 30 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे हैं. गनीमत रही कि पहिया निकलने के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और यात्रियों की जान बच गई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मनपा परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली और बसों के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बताया जा रहा है कि बस सड़क पर सामान्य रूप से चल रही थी, तभी अचानक उसका पहिया निकल गया. घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ. अब सवाल यह है कि चलती बस का पहिया आखिर कैसे निकल गया और सड़क पर उतारने से पहले बस की तकनीकी जांच किस स्तर पर की गई थी? 10 साल पुरानी बसें दे रहीं जवाब : मनपा परिवहन सेवा की शुरुआत वर्ष 2005 में 50 बसों के साथ हुई थी. आज परिवहन उपक्रम के बेड़े में कुल 131 बसें हैं, जिनमें 74 डीजल और 57 ई-बसें शामिल हैं. इनमें वर्ष 2015-16 में खरीदी गई डीजल बसें अब करीब 10 वर्ष का औसत जीवनकाल पूरा कर चुकी हैं.

18-20 लाख आबादी, जरूरत 350 बसों की, उपलब्ध सिर्फ 131

मीरा-भाईंदर की आबादी वर्तमान में करीब 18 से 20 लाख तक पहुंच चुकी है. शहर में लगातार नए आवासीय प्रकल्प विकसित हो रहे हैं. बड़ी संख्या में नागरिक रोजगार के लिए मुंबई, ठाणे, वसई-विरार और पालघर की ओर प्रतिदिन आवागमन करते हैं.

ऐसे में सार्वजनिक परिवहन शहर की बड़ी जरूरत बन चुका है. वर्तमान आबादी और यात्रियों की संख्या को देखते हुए शहर को कम से कम 350 बसों की आवश्यकता बताई जा रही है, जबकि मनपा के पास महज 131 बसें हैं. ऊपर से पुराने डीजल बस बेड़े में लगातार खराबियां यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं.

'पहिया निकलने' के बाद अब जवाबदेही का सवाल

कनकिया की घटना ने परिवहन विभाग के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बसों की फिटनेस जांच कितनी नियमित होती है? प्रत्येक बस सड़क पर उतारने से पहले उसकी तकनीकी जांच कौन करता है? पहिए और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों की सुरक्षा जांच के क्या मानक हैं? पुरानी बसों की समय पर मरम्मत और उनके पुर्जों को बदलने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

दो-तीन वर्षों में कई बसें हो जाएगी अनुपयोगी

इन बसों में लगातार तकनीकी खराबियां सामने आने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आशंका है कि अगले दो-तीन वर्षों में इनमें से कई बसें पूरी तरह अनुपयोगी हो सकती हैं. ऐसे में चलती बस का पहिया निकलने की घटना ने पुराने बस बेड़े के रखरखाव और नियमित फिटनेस जांच की व्यवस्था पर सवाल और गहरा दिए हैं.

मीरा-भाईंदर मनपा की डीजल बस सेवा ठेकेदार के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, डीजल और बसों के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की है. चलती बस का पहिया निकलना मेंटेनेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यदि जांच में लापरवाही सामने आती है, तो ठेकेदार की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता. मुझे विश्वास है कि महापौर डिंपल मेहता, विधायक नरेंद्र मेहता और मनपा आयुक्त इस मामले में तत्काल सख्त निर्णय लेंगे.

- एड. राजकुमार मिश्रा, सभापति एमबीएमटी

पर्यावरण अपराधों की हो निष्पक्ष जांच

200 से अधिक मामलों के स्पेशल ऑडिट की मांग

मीरा भाईंदर, (सं.) पर्यावरण अपराधों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को पर्यावरणविदों, छात्रों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक को ज्ञापन सौंपकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामलों की जांच में कथित अनियमितताओं की शिकायत की. ज्ञापन में भाईंदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर और नवघर पुलिस स्टेशन के एफआईआर की जांच पर सवाल उठाते हुए मुख्य आरोपियों को बचाने, त्रुटिपूर्ण चार्जशीट दाखिल करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया.

अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप

साथ ही बिना पर्यावरणीय अनुमति कार्यों को मंजूरी देने वाले संबंधित अधिकारियों की भी जांच की मांग की गई. प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2005 से 2026 के बीच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज 200 से अधिक मामलों का स्वतंत्र स्पेशल ऑडिट कराने, जांच की गुणवत्ता और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की. उनका कहना था कि अधिकांश मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिलने से पर्यावरण अपराधियों में कानून का भय खत्म हो रहा है.

29.25 करोड़ की लागत से भाईंदर पूर्व में बनाया जाएगा महिला भवन

भाईंदर. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र के भाईंदर पूर्व स्थित न्यू गोल्डन नेस्ट परिसर में महिलाओं और बाल कल्याण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक महिला भवन बनाया जाएगा. करीब 29.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी देने का प्रस्ताव 13 अगस्त 2026 को होने वाली महानगरपालिका महासभा में पेश किया जाएगा. मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा. महानगरपालिका के दस्तावेजों के अनुसार मौजे गोडदेव स्थित सर्वे नंबर 30, 327/1, 2, 4 आदि की कुल 1127 वर्ग मीटर नागरिक सुविधा क्षेत्र की जमीन सातबारा उतारे के साथ मनपा के कब्जे में है. इसी भूखंड पर वर्ष 2010 में विकास हक प्रमाणपत्र (टीडीआर) के बदले मनपा कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण की अनुमति दी गई थी. हालांकि, निर्माण कार्य केवल प्लिंथ (नींव स्तर) तक पहुंचने के बाद वर्षों तक अधूरा पड़ा रहा.

पुराने ठेकेदारों को एक्सटेंशन पर सवाल

एमबीएमसी के ठेका खत्म होने के बावजूद अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

मीरा-भाईंदर, (सं.) मीरा भाईंदर महानगरपालिका में ठेकों की अवधि खत्म होने के बाद भी पुराने ठेकेदारों को अवधि बढ़ाने के प्रस्तावों ने प्रशासन की निविदा प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस के गटनेता एवं नगरसेवक जय ठाकुर ने आरोप लगाया कि आयुक्त के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद समय पर निविदाएं नहीं निकालने से मनपा को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है. उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है.

तत्कालीन मनपा आयुक्त ने 3 अगस्त 2023 को जारी परिपत्रक में निर्देश दिए थे कि किसी भी पुराने ठेके की अवधि समाप्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नई निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. साथ ही तकनीकी व वित्तीय जांच में अनावश्यक देरी रोकने और निविदा लंबित रहने पर संबंधित विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश थे. इसके बावजूद अवधि समाप्त हो चुके ठेकों के सामने एक्सटेंशन आने के से प्रस्ताव प्रशासन स्थायी की कार्यप्रणाली समिति के पर सवाल उठ रहे हैं.

वाहन चालक ठेका, 31 मार्च को खत्म हुई अवधि, जुलाई में 6 महीने का एक्सटेंशन मनपा के विभिन्न विभागों के लिए वाहन चालक उपलब्ध कराने का ठेका मे. सिक्युअर 1 सिक्योरिटी सर्विसेज को दिया गया था. प्रति चालक 27,116 रुपए की न्यूनतम दर पर मंजूर इस ठेके का कार्यादेश 29 मार्च 2023 को जारी हुआ था.

मनपा का पैसा जनता का पैसा है. प्रशासनिक देरी का आर्थिक बोझ जनता पर नहीं डाला जा सकता. निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है.

- जय ठाकुर, गटनेता एवं नगरसेवक

MBMC की संपत्तियों के पट्टिकाओं पर सियासी 'सफाई' ; शिंदे-सरनाईक की तस्वीरें हटाने की तैयारी !

भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की 13 अगस्त को होने वाली महासभा में एक ऐसा प्रस्ताव सामने आने वाला है, जिसने शहर की सियासत गरमा दी है. भाजपा के सत्ता में आने के बाद प्रशासकीय कार्यकाल में विकसित की गई मनपा की विभिन्न संपत्तियों और आरक्षित भूखंडों की पट्टिकाओं पर लगी मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें हटाने की तैयारी है. प्रस्ताव में किसी नेता का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन निशाना प्रशासकीय काल में लगाई गई मंत्री प्रताप सरनाईक और तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीरों पर माना जा रहा है. प्रस्ताव में कहा गया है कि मनपा की ओर से निर्मित सार्वजनिक संपत्तियों और विकसित आरक्षित भूखंडों पर पहले मंत्रियों या जनप्रतिनिधियों के फोटो लगाने की परंपरा नहीं रही है. प्रशासकीय शासनकाल में पहली बार

प्रशासनिक नियमों और राजशिष्टाचार की अनदेखी करते हुए नामफलक पर तस्वीरें लगाई गईं. अब इन तस्वीरों को सम्मानपूर्वक हटाकर मनपा के मूल एवं अधिकृत नामफलक रखने की मांग की गई है.

विकास के श्रेय की पुरानी जंग को हवा

राजनीतिक जानकार इसे महज प्रशासनिक प्रोटोकॉल का मामला नहीं मान रहे हैं. मीरा-भाईंदर में भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक के बीच विकास कार्यों के श्रेय को लेकर लंबे समय से राजनीतिक खींचतान रही है. प्रशासकीय काल में सरनाईक के प्रभाव से विकसित परियोजनाओं पर उनकी और शिंदे की तस्वीरें लगी होना भाजपा के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में असहजता का कारण माना जाता रहा है. 13 अगस्त को प्रस्ताव महासभा के पटल पर आते ही हंगामे के आसार हैं।

मनपा का अजब कारनामा
पहले काम, फिर मंजूरी !

भाईंदर : मानसून में पेड़ गिरने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए मीरा भाईंदर मनपा ने 2 अतिरिक्त हाइड्रोलिक बूम लिफ्ट वाहन किराये पर लेकर पेड़ों की छंटाई शुरू कर दी, लेकिन 25 लाख रुपये के इस आपातकालीन खर्च को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. उद्यान विभाग ने 31 जुलाई को हुई स्थायी समिति की बैठक में 25 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा था. विभाग के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भारी बारिश की चेतावनी के बाद 7 जुलाई को महापौर की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन बैठक में अतिरिक्त बूम लिफ्ट वाहन किराये पर लेने का निर्णय लिया गया था. मनपा के पास पहले से 2 हाइड्रोलिक सीढ़ी वाहन हैं, लेकिन पूरे शहर में ऊंचे पेड़ों की समय पर छंटाई के लिए उन्हें पर्याप्त नहीं माना गया. इसलिए आपातकालीन स्थिति का हवाला देते हुए निविदा प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना 7 जुलाई से ही 60 और 80 फीट की 2 आर्टिकुलेटिंग बूम लिफ्ट चालक, ऑपरेटर और ईंधन सहित किराये पर लेकर काम शुरू कर दिया गया. दोनों वाहनों पर प्रतिदिन 2 शिफ्टों में करीब 66,080 रुपये खर्च हो रहे. इसके आधार पर 25 लाख रुपये के व्यय को उद्यान विभाग के वर्ष 2026-27 के वाहन खरीद के लिए मंजूर निधि से इस खर्च को मंजूरी देने की सिफारिश की गई.

प्रस्ताव को स्थाई समिति ने दी है मंजूरी

आयुक्त की स्वीकृति के बाद एम. के. इंफ्राटेक को कार्यादेश जारी किया गया और बाद में वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा गया.

प्रस्ताव को स्थाई समिति ने मंजूरी दे दी. वही एड. कृष्णा गुप्ता और कुछ स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जब कार्य 7 जुलाई से शुरू हो चुका था तो स्थायी समिति से बाद में मंजूरी लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है. साथ ही 25 लाख रुपये के आपातकालीन खर्च, बिना निविदा प्रक्रिया और ठेकेदार के चयन को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

जबकि मनपा प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत नागरिकों की सुरक्षा और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में लिया गया है.

500 करोड़ रुपये के कर्ज पर भिड़े सरनाईक-मेहता
पहले से ही भारी आर्थिक दबाव में है मीरा-भाईंदर मनपा

मीरा-भाईंदर. मीरा-भाईंदर में विकास के नाम पर 500 करोड़ रुपए का कर्ज अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. सूर्या प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के बाद सड़क निर्माण के 500 करोड़ के ऋण को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता फिर आमने-सामने हैं. एक तरफ सरनाईक मनपा की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर नए कर्ज पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर मेहता सरकार से तत्काल ऋण मंजूर करने की मांग कर रहे हैं. मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दोनों नेता सत्तारूढ़ खेमे से जुड़े हैं, लेकिन 500 करोड़ के सवाल पर उनकी राजनीतिक लाइन बिल्कुल अलग है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे पत्र में सरनाईक ने कहा कि शहर में सड़क निर्माण के लिए पहले ही करीब 500 करोड़ रुपए की निविदा प्रक्रिया के तहत काम कराया गया था. बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण कुछ काम अधूरे रहने का दावा भी उन्होंने किया है. सरनाईक का तर्क है कि मनपा पहले से भारी वित्तीय दबाव में है, ऐसे में सड़क निर्माण के बिल चुकाने के लिए नया 500 करोड़ का कर्ज लेना उचित नहीं होगा. उन्होंने एमएमआरडीए या मनपा की उपलब्ध निधि से सड़क कार्य पूरे करने का सुझाव दिया है. सरनाईक ने पूर्व में बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लेने की प्रक्रिया रुकने का भी उल्लेख किया है. उनके मुताबिक, तत्कालीन प्रशासन ने कर्ज नहीं लेने का रुख अपनाया था और बाद में बैंक की ऋण प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ सकी.

मेहता के अनुसार करीब 2 साल पहले मनपा को बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और एसबीआई समेत अन्य बैंकों से ऋण लेने की अनुमति मिली थी. बैंक ऑफ बड़ौदा से 500 करोड़ का ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन तत्कालीन आयुक्त संजय काटकर के कर्ज नहीं लेने के निर्णय के बाद मामला रुक गया. बाद में दोबारा प्रयास हुआ. मेहता का दावा है कि प्रस्ताव आरबीआई तक पहुंचने के बाद आपत्ति सामने आई और बैंक को ऋण नहीं देने के निर्देश दिए गए. इसके बाद इंडियन बैंक से संपर्क किया गया और उसने 500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी.

ऋण मंजूर नहीं हुआ तो मेहता करेंगे आंदोलन

भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने पिछले मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर दबाव बढ़ाया.

उनका दावा है कि इंडियन बैंक ने मनपा के शहरी सड़क निर्माण के पहले चरण के लिए 500 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार की अंतिम अनुमति नहीं मिलने के कारण राशि अभी तक मनपा को नहीं मिली है.

मेहता ने सरकार को 10 अगस्त तक ऋण मंजूर करने की डेडलाइन दी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि मंजूरी नहीं मिली तो भाजपा सोमवार सुबह 11 बजे घोड़बंदर राज्य महामार्ग स्थित फाउंटेन होटल के पास आंदोलन करेगी.

बैंक बदले, लेकिन 500 करोड़ की फाइल नहीं चली

शिंदे के विभाग पर भी मेहता का निशाना

मेहता ने दावा किया कि ऋण प्रस्ताव नगर विकास विभाग में लंबित है. विभाग का प्रभार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास होने का हवाला देते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव रोके जाने पर सवाल उठाए. इस बहाने उन्होंने सरनाईक की भूमिका पर भी राजनीतिक निशाना साधा था.

मनपा पर पहले से आर्थिक बोझ है. नया 500 करोड़ का कर्ज नागरिकों पर अतिरिक्त भार डालेगा. सड़कें एमएमआरडीए या मनपा की निधि से पूरी हों. - प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

इंडियन बैंक 500 करोड़ का ऋण 66 मंजूर कर चुका है. केवल सरकारी अनुमति बाकी है. मंजूरी में देरी से सड़क निर्माण प्रभावित हो रहा है. - नरेंद्र मेहता, विधायक

लगातार हो रहे हादसों को लेकर सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश
MBMC करेगी अब घोड़बंदर रोड की मरम्मत

भाईंदर : घोड़बंदर रोड पर गायमुख से फाउंटेन होटल तक जर्जर सड़क और लगातार हो रहे हादसों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने मीरा भाईंदर मनपा (एमबीएमसी) को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं. नगर विकास विभाग ने 30 जुलाई को इस संबंध में मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा को आदेश जारी किया है. 28 जुलाई को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया गया कि गायमुख से फाउंटेन तक का सड़क मार्ग लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से मनपा को हस्तांतरित किया जा चुका है.

इसलिए इस सड़क के रखरखाव और मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी अब मीरा भाईंदर मनपा की होगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल सड़क मरम्मत के लिए अलग से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना संभव नहीं है और मनपा को चालू वित्तीय वर्ष की स्वीकृत निविदा एवं उपलब्ध निधि से ही तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करना होगा.

MMRDA करेगा सड़क चौड़ीकरण का कार्य

बैठक में यह भी तय किया गया कि गायमुख से फाउंटेन तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) करेगा, जबकि इसके लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी मीरा भाईंदर मनपा निभाएगा. चौड़ीकरण से जुड़ी आवश्यक जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं. परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को सड़क की बदहाल स्थिति के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की देरी न करने के निर्देश दिए.

सड़कों के गड्ढों के विरोध में सांकेतिक रूप से चंदा जुटाएंगे नागरिक

इस बीच शुक्रवार (31 जुलाई) की सुबह करीब 10 बजे एन एच-48 पर गायमुख, काजूपाड़ा, कार्पे कंपाउंड और वर्सोवा क्षेत्र में बड़े गड्ढों के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और ट्रैफिक रेंगता रहा. स्थिति को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने निजी जेसीबी और डंपर की मदद से मौके पर ही गड्ढे भरने का काम शुरू कराया, जिसके कारण यातायात धीमी गति से चलता रहा. ऐसी जानकारी काशीमीरा ट्रैफिक शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सतीश शिवरकर ने दी. शहर की जर्जर सड़कों और गड्ढों की समस्या के विरोध में सोमवार को समाजसेवी सज्जी आई पी और एडविन गोंसालविस द्वारा एक अनोखी सामाजिक पहल की जाएगी. इस अभियान के तहत लोगों से सांकेतिक रूप से चंदा (धनराशि) एकत्र किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य सड़कों की बदहाल स्थिति की ओर मीरा भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है. नागरिकों से एकत्र की गई पूरी राशि के साथ एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा जाएगा.

सड़क किनारे लगेंगे 3944 पेड़
3 करोड़ के प्रस्ताव को मनपा की मंजूरी

भाईंदर : मीरा भाईंदर मनपा की 31 जुलाई को हुई स्थायी समिति की बैठक में शहर की सड़कों के दोनों किनारों पर 3944 पेड़ लगाने और ढाई वर्ष तक उनकी देखरेख से जुड़े करीब 3 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. प्रस्ताव में वृक्षारोपण के साथ नियमित सिंचाई, खाद, छंटाई, खरपतवार हटाने, कीटनाशक छिड़काव और पौधों के रखरखाव का कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराने का प्रावधान है. इस योजना को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं. मनपा प्रशासन के अनुसार विशेष आम सभा के 27 मार्च 2026 के प्रस्ताव के तहत 2.99 करोड़ 95 हजार 339 रुपये की लागत से ई-टेंडर जारी किया गया था. सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार की निविदा 21 जून 2026 को मंजूर की गई.

करीब 3 करोड़ रुपये खर्च कर 3944 पेड़ लगाने की योजना बनाई जा रही है. इसके अनुसार एक पेड़ पर करीब 7605 रुपए का खर्च पड़ रहा है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये पेड़ किन-किन स्थानों पर लगाए जाएंगे. जब तक वृक्षारोपण के स्थान, प्रजातिवार वितरण और कार्य योजना सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक इतनी बड़ी राशि के प्रस्ताव पर सवाल उठना स्वाभाविक है. पूरे मामले में पारदर्शिता बरतते हुए विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग हमने की है. - जय ठाकुर, नगरसेवक व समूह नेता कांग्रेस.

इंद्रलोक में आवारा कुत्तों की फीडिंग पर बढ़ा विवाद

भाईंदर : भाईंदर पूर्व के इंद्रलोक परिसर में सार्वजनिक एवं आवासीय क्षेत्रों में कथित तौर पर नियमों के विपरीत की जा रही आवारा कुत्तों की फीडिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. स्थानीय संजय संतोष दुबे ने मीरा-भाईंदर मनपा आयुक्त, मीरा-भाईंदर-वसई-विरार के पुलिस उपायुक्त, महापौर डिम्पल मेहता और उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल को शिकायत देकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है. नागरिकों का आरोप है कि इंद्रलोक परिसर में सड़क, फुटपाथ, सोसायटी के प्रवेशद्वार, पार्किंग क्षेत्र, बच्चों के खेलने की जगह और नागरिकों की आवाजाही वाले स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा अनियमित तरीके से आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है. इससे कुत्तों के झुंड जमा होने, खाद्य अवशेष एवं गंदगी फैलने तथा बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य नागरिकों की आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति बन रही है. दुबे ने अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ऐनीमल बर्थ कंट्रोल 2023 के नियम 20 का हवाला देते हुए प्रत्येक वार्ड में निर्धारित डॉग फीडिंग स्पॉट और फीडिंग टाइम तय करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि फीडिंग स्पॉट बच्चों के खेलने के स्थान, प्रवेश-निकास, सीढ़ियों तथा बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की नियमित आवाजाही वाले क्षेत्रों से दूर होने चाहिए.

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com